बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 210 ● नई दिल्ली ● शनिवार 06 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली हाईकोर्ट से कॉकरोच जनता पार्टी को राहत, प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं को उठाया गया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में राहत देने से मना कर दिया, जिससे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के आयोजन पर फिलहाल रोक नहीं लग सकी। याचिका में यह दलील दी गई थी कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि, कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता को नहीं माना और इस संबंध में कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।

रणदीप सुरजेवाला को जन्मदिन की शुभकामनाएं, संगठन को मजबूत करने में निभा रहे अहम भूमिका

नई दिल्ली। (ए, के, चौधरी)अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, कर्नाटक प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के जन्मदिन पर किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी, रिपब्लिकन मजदूर संगठन तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में delhi pradesh Congress ke vice president sh.surender kumar ने कहा कि श्री सुरजेवाला ने कांग्रेस संगठन को सशक्त बनाने, जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व एवं राजनीतिक अनुभव से पार्टी कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रेरणा मिलती है। राष्ट्र टाइम्स के संपादक एवं एक्रिडिटेड

जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी अपने संदेश में कहा कि, ÷श्री रणदीप सुरजेवाला एक कुशल वक्ता, अनुभवी राजनेता और जनसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व हैं। उनके जन्मदिन पर मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर जनकल्याण के कार्यों की सफलता की कामना करता हूं।÷

वहीं किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पत्रकार विजय कुमार भारती ने कहा कि, ÷श्री रणदीप सुरजेवाला का राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाया है। उनके जन्मदिन पर हम उनके स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घ जीवन की मंगलकामना करते हैं। इस अवसर पर इन्द्रजीत सिंह, वरुण दुका सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भी श्री सुरजेवाला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

मानवता और न्याय के सामने एआई सबसे बड़ी कानूनी चुनौती, सीजेआई बोले- इस दशक के फैसले तय करेंगे भविष्य

नई दिल्ली । भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एआई को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि एआई अब केवल एक कल्पनात्मक तकनीक नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन चुकी है और यह अंतरराष्ट्रीय कानून के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस दशक में लिए जाने वाले निर्णय तकनीक, शक्ति, स्वतंत्रता और न्याय के बीच भविष्य के संबंधों को निर्धारित करेंगे।

कानून की जिम्मेदारी बताई

ब्रिटेन के बर्कबेक, लंदन विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल लॉ विषय पर आयोजित सार्वजनिक व्याख्यान में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि तकनीक न तो स्वभाव से अच्छी होती है और न ही बुरी। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि समाज उसे किस कानूनी, राजनीतिक और नैतिक ढांचे के भीतर उपयोग करता है। कानून की जिम्मेदारी तकनीकी प्रगति का विरोध करना या उसके सामने बिना सवाल झुक जाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी शक्ति संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक वैधता और मानवीय गरिमा के प्रति जवाबदेह बनी रहे।

एआई कैसे सभी क्षेत्रों को कर रहा प्रभावित?

उन्होंने कहा कि एआई शासन, व्यापार, युद्ध, संचार, सार्वजनिक प्रशासन और यहां तक कि न्यायिक एवं संप्रभु शक्तियों के इस्तेमाल को भी तेजी से प्रभावित कर रहा है। सरकारें अब कल्याणकारी योजनाओं के आवंटन, आव्रजन आवेदनों के मूल्यांकन, सीमा निगरानी, वित्तीय नियमन और पुलिसिंग जैसे कार्यों में एल्गोरिदमिक प्रणालियों का उपयोग कर रही हैं। वहीं सेनाएं स्वायत्त सैन्य क्षमताओं का विकास कर रही हैं और अदालतें एआई से जुड़े साक्ष्यों, स्वचालित निर्णयों तथा डिजिटल न्यायिक प्रक्रिया जैसे सवालों से जूझ रही हैं।

एआई न्यायिक व्यवस्था के लिए कैसे अवसर है?

सीजेआई ने कहा कि एआई न्यायिक व्यवस्था के लिए एक अवसर भी है। यदि इसका जिम्मेदारीपूर्वक और मानवीय निगरानी में उपयोग किया जाए तो यह कानूनी शोध, केस प्रबंधन, अनुवाद, ट्रांसक्रिप्शन, दस्तावेजों के वर्गीकरण और न्यायिक मिसालों की पहचान जैसे कार्यों में मदद कर सकता है। इससे मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्याय तक लोगों की पहुंच बेहतर होगी।

एआई किसे और कैसे दे रही चुनौती?

उन्होंने यह भी कहा कि पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून क्षेत्रीय सीमाओं पर आधारित रहा है, लेकिन एआई इन अवधारणाओं को चुनौती देता है। एआई मॉडल कई देशों के डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं, अलग-अलग देशों में स्थित कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या संप्रभुता, मानवाधिकार और जवाबदेही जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून के मौजूदा सिद्धांत इस नई तकनीकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं या फिर नई कानूनी सोच की जरूरत पड़ेगी।

एआई का भविष्य कैसे तय होगा?

अपने संबोधन के अंत में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एआई का भविष्य केवल तकनीकी नवाचार से नहीं, बल्कि मानवता द्वारा किए जाने वाले कानूनी और नैतिक विकल्पों से तय होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी क्षमता को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि ऐसे माहौल में कानूनी जवाबदेही को बनाए रखना है जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया तेजी से एल्गोरिदम के माध्यम से संचालित हो रही है। अगर जवाबदेही बिखर गई, तो न्याय और उत्तरदायित्व की अवधारणा ही कमजोर पड़ सकती है।

दक्षिणी दिल्ली और करावल नगर में शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, कई दुकानें की गईं सील

नई दिल्ली । दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में की जा रही है। दक्षिणी दिल्ली के घिटोरनी में अनधिकृत निर्माण तोड़े गए हैं। इसके साथ ही, कई दुकानें भी सील की गई हैं। पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में भी एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। दिल्ली नगर निगम हौज खास गांव में भी सीलिंग की कार्रवाई कर रही है। मालवीय नगर में हुई भीषण अग्नि त्रासदी ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। इस घटना के तुरंत बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने एक आपात बैठक बुलाई थी। जिसमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की गई। प्रशासन ने न केवल हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, बल्कि बृहस्पतिवार यानी 4 जून से पूरी दिल्ली में एक महीने का सघन प्रवर्तन अभियान शुरू करने का फैसला लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 जून से शुरू होने वाला यह अभियान दिल्ली के सभी होटलों, लॉज, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों और रेस्टोरेंट्स में फायर सेफ्टी मानकों की जांच होगी। दिल्ली सरकार के गृह विभाग को इस पूरे अभियान के लिए नोडल विभाग घोषित किया गया है, जो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। इस अभियान की निगरानी संयुक्त रूप से मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर करेंगे। कार्रवाई से पहले बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस में स्वीकृत संख्या से अधिक कमरे पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस, एमसीडी और पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से होटल एसोसिएशनों के साथ बैठकें करेंगे और उन्हें लाइसेंस की शर्तों और फायर सेफ्टी नियमों का कड़ाई से पालन करने की अंतिम चेतावनी देंगे। जो संस्थान मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें न केवल सील किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मीटिंग में तय हुआ है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने फायर सेफ्टी उपकरण, पानी के टैंक और सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया। खास बात यह है कि फायर सेफ्टी नियमों को डिजिटल रूप में सभी व्यावसायिक इमारतों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को भेजा जाएगा, ताकि वे खुद अपनी तैयारी की जांच कर सकें। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने जनता को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया है। फायर विभाग एक सप्ताह के भीतर एक समर्पित हेल्पलाइन और ईमेल आईडी जारी करेगा। इसके माध्यम से नागरिक अपने आसपास के उन भवनों की शिकायत कर सकेंगे जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं।

छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों में उचित हिस्सेदारी देने की मांग

एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीबीसी से विज्ञापन वितरण में पारदर्शिता, समान अवसर और छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के लिए न्यायसंगत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग की

नई दिल्ली। (इंद्रजीत सिंह) देश के छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों के वितरण में उचित प्रतिनिधित्व और समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग को लेकर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि छोटे एवं मध्यम समाचार पत्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और जागरूकता अभियानों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए विज्ञापन वितरण व्यवस्था में उनकी भागीदारी को उचित महत्व मिलना चाहिए। एसोसिएशन ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) से विज्ञापन आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और संतुलित बनाने की मांग की है। एसोसिएशन ने आग्रह किया है कि विज्ञापन बजट में छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के लिए भी उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके।

एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राष्ट्र टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा, ÷छोटे और मध्यम समाचार पत्र लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये स्थानीय समस्याओं, जनहित के मुद्दों और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का माध्यम हैं। ऐसे में सरकारी विज्ञापनों के वितरण में इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और उन्हें न्यायोचित अवसर मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बढ़ती मुद्रण लागत, वितरण व्यय और अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण छोटे एवं मध्यम समाचार पत्र गंभीर वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकारी विज्ञापनों का पारदर्शी और संतुलित वितरण न केवल इन समाचार पत्रों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा, बल्कि विविध और स्वतंत्र मीडिया व्यवस्था को भी मजबूती देगा। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि छोटे एवं मध्यम समाचार पत्र देश के दूरदराज़ और स्थानीय क्षेत्रों में सूचना के प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए विज्ञापन आवंटन नीति में उनकी भूमिका और योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से इस विषय पर सकारात्मक पहल करने का आग्रह करते हुए कहा कि छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा विज्ञापन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता, समान अवसर और न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

हम पूंजीवादी व्यवस्था में जी रहे हैं

देशभर में इन दिनों भयावह हत्याकांड को लेकर सनसनी मची हुई है। आज के समय में हर कोई भाग-दौड़ में लगा हुआ है। इसी भाग-दौड़ की वजह से लोगों के पास अब समय और धैर्य दोनों की ही कमी होने लगी है। आज के दौर में लोग अपने जीवन में सब बहुत जल्दी हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपनी इसी कोशिश के बदौलत लोग न सिर्फ जल्दी खुशी हासिल कर लेते हैं, बल्कि रिश्ते में काफी जल्दी सामंजस्य भी बना लेते हैं लेकिन ऐसे रिश्तों में अक्सर धैर्य की कमी रह जाती है। ऐसे रिश्ते में रहने वाले लोग न कुछ सीखना चाहते है, न एडजस्ट करना चाहते है और न ही दूसरे की बात को समझना चाहते है। ऐसे हालातों में रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है, जो आगे चलकर तनाव और गुस्से का रूप लेती है। साथी, प्रेमी या फिर पति की हत्या कर उसके शव को टुकड़ों में काटना-ये कैसी सनक है। प्यार कभी हिंसा के रास्ते पर लेकर नहीं जाता है। क्या ऐसी दिल दहला देने वाली हत्याएं 'रिश्तों की मौत' नहीं है एक पति की हत्या उसकी पत्नी ने कर दी। पति की हत्या करने के बाद अपने ब्वायफ्रेंड के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके चार टुकड़े कर दिये। 'रिश्तों की मौत' का ये अकेला मामला नहीं है, इससे पहले श्रद्धा वालकर समेत कई ऐसी खौफनाक वारदात सामने आ चुकी हैं। आखिर कोई इस हद तक कैसे गुजर जाता है कि अपने साथी की बेरहमी से हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता यूपी के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के चर्चित आरव हत्याकांड में रविवार को जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस पर मासूम के शव का पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टरों के द्वारा की गई इस जांच में हैवानियत की जो कड़वी सच्चाई सामने आई है, उसने डॉक्टरों को भी झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की बर्बरता के कारण डेढ़ साल के आरव के सिर और छाती की सभी हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थीं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने चोटों की तीव्रता के आधार पर अनुमान लगाया है कि जब आरोपी विरान ने मासूम को पहली बार हवा में उछालकर पक्की सड़क पर दे मारा, तभी आरव के स्कैल्प (खोपड़ी) के सभी जोड़ खुल गए थे और वह तुरंत अचेत (बेहोश) हो गया था। विरान उर्फ जितेंद्र पाठक ने रिश्ते की भाभी रती से शादी करने की जिद पूरी न होने पर उसके डेढ़ साल के मासूम बेटे आरव को सड़क पर बेरहमी से आठ बार पटक-पटककर मार डाला था। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। मूल रूप से अराव निवासी रती देवी की शादी फरवरी 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुई थी। पति से अनबन के कारण वह पांच महीने से मायके में रह रही थीं। इसी बीच सुमित के फुफेरे भाई विरान उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखूपुर, बदायूं ने रती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे रती ने ठुकरा दिया था। एक आदमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने दो मासूम बेटों और पत्नी को काट डाला। अपने ही बच्चों का गले रेतते हुए इस जुल्मि बाप को ज़रा भी तरस नहीं आया। सच यह है कि आज हम इतने स्वार्थी और एकांतवादी होते जा रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी मनमानी करने के लिये हम रिश्तों-नातों को कच्चे धागों की तरह तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। अगर थोड़ा झगड़ा और रूठना-मनाना कर ये सम्बन्ध फिर से प्यार मोहब्बत की डोर में बंध जायें तो फिर भी आपसी तालमेल और साझा जीवन का एक रास्ता निकल सकता था लेकिन आज तो हालत यह हो गयी है कि साझा परिवार टूटते जा रहे हैं। कुछ लोग तो शादी से पहले ही लड़के के परिवार के सामने यह शर्त रख देते हैं कि उनकी लड़की शादी के बाद अलग रहना पसंद करेगी। यह अजीब बात है कि लगभग सभी मां-बाप अपनी लड़की को यह समझाकर ससुराल भेजते हैं कि शादी के बाद अपने पति को अपने हिसाब से चलाने की पूरी कोशिश करना और मौका देखते ही अलग हो जाना जिससे सास-ससुर और ननद, भावज, जेठ-जेठानी और देवर-देवरानी की सेवा और जिम्मेदारी से बचा जा सके जबकि अपने घर आने वाली लड़के की बहू से सौ प्रतिशत यह आशा करते है कि वह अपने मायके को भूलकर लड़के के पूरे परिवार के हिसाब से चले। दर्जन दो दर्जन से चार पांच लोगों की छोटी यूनिट में आधुनिक प्रगतिशील माता-पिता की बोल्ड सोच के बच्चे चाहते हैं कि उनका अपना निजी कमरा, फोन, टीवी और अलग कंप्यूटर हो। कमरे में अटैच टॉयलेट बाथरूम हो। आज के समय में फिल्मों, वेब सीरीज और यहां तक कि गेम्स में भी हिंसात्मक और अपराध आधारित कंटेंट दिखाने का ट्रेंड सा बन गया है। फिल्मों और सीरीज में लगातार दिखाए जाने वाले ऐसे सीन ने लोगों के दिमाग में एक गहरी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। यह फिल्में और सीरीज न सिर्फ लोगों को अपराध दिखाते है, बल्कि अपराधियों को एक हीरो की तरह पेश कर उनका गुणगान भी करती है। जिसमें न सिर्फ अपराध दिखाया गया है, बल्कि इसे अंजाम देने के तरीकों को भी करीब से बताया गया है। अगर लोग लगातार इस तरह के सीन देखते रहेंगे तो उनके मन में यह धारणा बन जाएगी कि रील लाइफ की ही तरह रियल लाइफ में भी हिंसा का सहारा लेना बिल्कुल सही है। रिश्ते में गुस्से और हिंसा की सबसे मुख्य वजह होती है उम्मीदों का पूरा न होना। अक्सर किसी रिश्ते में लोग एक-दूसरे से कई तरह की इच्छाएं और उम्मीदें रखते है लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब आप या आपके पार्टनर इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते है। ऐसे में रिश्ते में मौजूद यह अपूर्ण उम्मीदें अक्सर गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदल जाती है। ऐसे में रिश्ते में रहने की वजह से कई बार लोग मेंटल स्ट्रेस से भी जूझने लगते है। लगातार टूटती उम्मीदों की वजह से यह गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि कई बार हिंसा का रूप ले लेता और बाद में यह गुस्सा किसी बड़े अपराध को वजह बन जाता है। जब हम पूंजीवादी व्यवस्था में जी रहे है तो उसकी बुराइयां और कमियां भी हमको झेलनी होंगी। यह नहीं हो सकता कि हम गुड़ खायें और गुलगुलों से परहेज करें। शिक्षा के साथ-साथ जब तक हम सही शिक्षा, समाज व नैतिकता के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक खून के रिश्तों का खून ऐसे ही नहीं बहता रहेगा बल्कि यह वारदातें और खतरनाक हादसे बढ़ते ही जायेंगे।

आई.एस.आई. का फर्जी सिखों के सहारे भारत विरोधी अभियान

पाकिस्तान द्वारा एक ओर सिख समुदाय के प्रति उदारवादी नीति अपनाते हुए सिख मसलों को गंभीरता से लेने की बात की जाती है, सिखों को उनके धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए समय-समय पर पाकिस्तान आने का न्यौता दिया जाता है, मगर वहीं दूसरी ओर पिछले लगभग 13 वर्षों से पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व को भारत के विपरीत जाकर अलग तारीखों से मनाया जाता रहा है। इस बार शहीदी पर्व 18 जून को आ रहा है और समूचा संसार इसी दिन शहीदी पर्व को मनाएगा परन्तु पाकिस्तान में एक बार फिर से 16 जून को शहीदी पर्व मनाया जा रहा है, हलांकि इस बार यह देखने को मिला है कि भारत से जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के द्वारा 18 जून को ही शहीदी पर्व समागम किए जायेंगे, जिसकी जानकारी शिरोमणि कमेटी द्वारा सरकार को लिखे पत्र से प्राप्त हुई है। देखा जाए तो भारत की सिख जत्थेबंदियों की बड़ी जीत माना जा सकता है, जिसमें अहम रोल दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, महासचिव जगदीप सिंह काहलो और विशेष तौर पर परमजीत सिंह चंडोक ने अदा किया है। दूसरी ओर पिछले लंबे समय से पाकिस्तान भारत विरोधी दुष्प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाता रहा है। कभी आतंकवाद के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के जरिए और कभी धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वह न केवल चिंताजनक है बल्कि पूरी सिख कौम की धार्मिक पहचान और सम्मान पर सीधा हमला भी है। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. से जुड़े तत्व भारत, भारतीय सेना, भारतीय मीडिया और देश के सामाजिक ताने-बाने के खिलाफ जहर उगलने के लिए मुस्लिम और ईसाई युवाओं को सिखों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी सिख पहचान बनाकर भारत विरोधी वीडियो और सामग्री प्रसारित की जा रही है, ताकि दुनियाभर में यह भ्रम फैलाया जा सके कि सिख समुदाय भारत के खिलाफ खड़ा है। यह केवल फर्जी प्रचार नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र प्रतीत होता है। लाहौर के काशिफ अली आशिक उर्फ काशिफ राजा द्वारा "सरदार एस.के.पी." नाम से कथित रूप से संचालित फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट इसका एक उदाहरण बताया जा रहा है। आरोप है कि इस पहचान के माध्यम से दर्जनों भारत विरोधी वीडियो प्रसारित किए गए। इसी प्रकार सरदार मुहम्मद बिलावल नामक व्यक्ति द्वारा "सिद्धू 39 वाला" नाम से सिख स्वरूप धारण कर सोशल मीडिया गतिविधियां चलाने पर भी पाकिस्तानी सिखों ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले को स्वयं पाकिस्तान के सिख समुदाय ने उठाया है। पाकिस्तान के सिख नेताओं और सामाजिक संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि गैर-सिख व्यक्तियों द्वारा पगड़ी और सिख पहचान का इस्तेमाल कर झूठी प्रसिद्धि हासिल करना तथा राजनीतिक या धार्मिक एजेंडा चलाना पूरी सिख बिरादरी के सम्मान के खिलाफ है। यह विरोध किसी दूसरे देश द्वारा नहीं, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले सिखों द्वारा उठाया गया है जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार रोका जा सकता था आज भी यह सवाल उठता है कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार टाला जा सकता था क्या पंजाब को उस भयावह दौर से बचाया जा सकता था और क्या कुछ राजनीतिक नेताओं की गलत रणनीतियों ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि अंततः सेना को दरबार साहिब परिसर में प्रवेश करना पड़ा पंजाब में तनाव 1978 के निरंकारी-सिख संघर्ष के बाद धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ा। इसी दौरान पंजाब केसरी के संस्थापक सम्पादक लाला जगत नारायण जी एक प्रमुख आवाज बनकर सामने आए। वह पंजाब केसरी और हिंद समाचार समूह के संस्थापक थे। लाला जगत नारायण जी खुलकर उग्रवाद, अलगाववाद और भिंडरांवाले की नीतियों की आलोचना करते थे। उन्होंने अपने लेखों में पंजाब में बढ़ती कट्टरता और हिंसा के खिलाफ लगातार लिखा। यही कारण था कि वह उग्रवादी तत्वों के निशाने पर आ गए। 9 सितंबर, 1981 को उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या ने पूरे पंजाब में सनसनी फैला दी और हिंदू-सिख संबंधों में तनाव और बढ़ गया। जरनैल सिंह भिंडरांवाले की इस हत्या के मामले में संदेह के आधार पर गिरफ्तारी भी हुई, हालांकि बाद में तत्कालीन केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले और उन्हें रिहा कर दिया गया। भिंडरांवाले की लोकप्रियता उनकी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद और अधिक बढ़ गई। चार दशक बाद आज भी एक सवाल वही उठता है कि दरबार साहिब परिसर के अंदर हथियारों और गोला-बारूद का इतना बड़ा जखीरा कैसे पहुंचा। यह तथ्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 1983-84 तक परिसर के कुछ हिस्सों को किलेबंद कर दिया गया था और हथियारबंद लोग वहां मौजूद थे लेकिन यह कैसे हुआ, इस पर आज भी विवाद है। कोई सर्वमान्य न्यायिक निष्कर्ष नहीं है जो किसी एक संस्था या व्यक्ति को निर्णायक रूप से जिम्मेदार ठहराए। यदि शुरुआती चरण में ही स्थिति पर नियंत्रण किया जाता तो शायद इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। कृपाण आस्था का प्रतीक, विवाद का नहीं ब्रिटेन में हाल ही में कृपाण को लेकर छिड़ी बहस ने एक बार फिर धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक सुरक्षा और सामुदायिक जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को

सम्पादकीय...

बिखरती तृणमूल

देश के दो राज्यों में कल दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों ने भविष्य की राजनीति की तरफ इंगित करते हुए साफ किया कि एक तरफ जहां बलशाली क्षेत्रीय दलों का ह्रास हो रहा है वहीं दूसरी ओर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपनी विचारधारा की ताकत पर अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि राजनीति में सकल रूप से क्षेत्रीय दलों का प्रभाव जिस तरह पिछले कुछ दशकों खास कर 90 के दशक के बाद बढ़ा था उसके पीछे कोई निश्चित सैद्धान्तिक विचारधारा काम नहीं कर रही थी, बल्कि कोरी सत्ता की समीकरणें प्रमुख भूमिका निभा रही थीं और लगातार राज कर रही कांग्रेस पार्टी के शिथिल रवैये के प्रति लोगों में उत्पन्न हुई उदासीनता को भुना रही थीं। एक तरफ दक्षिण के राज्य कर्नाटक में कल कांग्रेस के नये मुख्यमन्त्री श्री डी.के. शिवकुमार ने पद व गोपनीयता की शपथ अपने राज्य के राजनीति के महाबली के रूप में स्थापित श्री सिद्धारमैया को गद्दी से उतार की तो दूसरी तरफ पूर्व के राज्य प. बंगाल में एक महीने पहले तक राज कर रहीं जन नेता के रूप में जानी जाने वाली सुश्री ममता बनर्जी के विरुद्ध उनके अपने ही दल तृणमूल कांग्रेस में हुए व्यापक विद्रोह को वैधानिकता प्राप्त हुई। ममता दीदी के विरुद्ध यह विद्रोह उन्हीं की पार्टी के एक नेता ऋतुब्रत बनर्जी ने किया और घोषणा की कि राज्य विधानसभा में हाल के चुनावों में चुने गये पार्टी के 80 विधायकों में से 60 उनके साथ हैं अतः वही विधानमंडल दल के नेता हैं। उनके इस दावे को विधानसभा के अध्यक्ष ने जायज पाया और उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे दी। जबकि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व ममता दी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अध्यक्ष को अपनी पार्टी की ओर से सूचित किया था कि उनकी पार्टी का विधानमंडल दल श्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय को अपना नेता चुनता है अतः उन्हें नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जाना चाहिए परन्तु इस पत्र के बारे में श्री ऋतुब्रत बनर्जी के साथ एक अन्य विधायक ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी द्वारा भेजे गये पत्र पर उनके जाली दस्तखत हैं और इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष के साथ लोकसभा अध्यक्ष को भी कर दी क्योंकि अभिषेक बनर्जी प. बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा सदस्य हैं। दूसरी तरफ राज्य विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस के 58 विधायकों ने श्री ऋतुब्रत बनर्जी के पक्ष में अध्यक्ष को जो पत्र भेजा उसमें साफ लिखा कि वे ही तृणमूल कांग्रेस का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि उनके पास दो-तिहाई विधायकों से अधिक का बहुमत प्राप्त है और ममता दीदी उनकी नेता हैं। इससे स्पष्ट है कि ममता दी की पार्टी में जो विद्रोह हुआ है वह वैधानिक नियमों की परिधि में सर्वथा जायज है। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को इस बात से मतलब होता है कि किसी पार्टी के विधानमंडल दल में किस गुट का बहुमत है। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला उदाहरण यह है कि 1969 में जब स्वर्गीय इन्दिरा गांधी ने बैंक राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर विभाजन किया तो पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। एक नई कांग्रेस बनी और दूसरी संगठन कांग्रेस बनी। इन्दिरा जी की नई कांग्रेस सत्ता में थी और संगठन कांग्रेस के सांसद विपक्ष में बैठे।

अन्नामलाई का नई पार्टी बनाने का निर्णय आवेश में लिया गया फैसला नहीं, लंबे चिंतन का निष्कर्ष दिखाई देता है

तमिलनाडु की राजनीति में एक नया भूचाल उस समय आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा देकर अपने नए राजनीतिक आंदोलन की घोषणा कर दी। यह फैसला तमिलनाडु की जमी हुई राजनीतिक संस्कृति को चुनौती देने वाला एक बड़ा संदेश है। अन्नामलाई ने जिस साफगोई, साहस और वैचारिक दृढ़ता के साथ अपने फैसले को सामने रखा है, उससे यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब किसी दल के सीमित दायरे में नहीं, बल्कि तमिल समाज की व्यापक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप में उभरना चाहते हैं। अन्नामलाई ने खुलकर कहा कि उनके भीतर लंबे समय से यह संघर्ष चल रहा था कि वह पहले भारतीय हैं या तमिल। यह बयान केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के उस मूल द्वंद्व को सामने लाता है जिसमें राष्ट्रीय दलों को अक्सर क्षेत्रीय अस्मिता के सामने संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि चार दिसंबर 2025 को ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व को इस्तीफे का फैसला बता दिया था, लेकिन उनसे चुनाव तक रुकने का अनुरोध किया गया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को लेकर कितना सजग था। पूर्व पुलिस अधिकारी रहे अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी में सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से प्रवेश किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहते हुए उन्होंने कभी तमिलनाडु की पहचान से समझौता नहीं किया। पिछले अठारह महीनों में संगठनात्मक मामलों को लेकर उनकी असहमति लगातार बढ़ती गई। यही कारण है कि उन्होंने अब एक स्वतंत्र राजनीतिक रास्ता चुनने का फैसला किया है। यह निर्णय किसी आवेश का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे चिंतन और रणनीतिक तैयारी का हिस्सा दिखाई देता है। अन्नामलाई ने अपने नए आंदोलन वी द लीडर की घोषणा करते हुए साफ कर दिया कि उनका उद्देश्य केवल एक और राजनीतिक दल खड़ा करना नहीं, बल्कि राजनीति की भाषा और संस्कृति को बदलना है। उन्होंने परिवारवाद और व्यक्तिपूजा की राजनीति पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी विधायक, सांसद या मंत्री का पद स्थायी नहीं होना चाहिए। यह बयान तमिलनाडु की उस परंपरागत राजनीति पर करारा प्रहार है जिसमें कुछ परिवारों और सीमित चेहरों के इर्दगिर्द सत्ता घूमती रही है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्नामलाई ने राजनीति में तकनीकी विशेषज्ञों, युवाओं और सामान्य नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने युवाओं से राजनीति में आने की अपील करते हुए कहा कि अब आम आदमी की नई पीढ़ी की राजनीति की नींव रखी जा रही है। यह सोच उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग करती है। देखा जाये तो तमिलनाडु में जहां लंबे समय से भावनात्मक नारों और जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीति चलती रही है, वहां अन्नामलाई प्रशासनिक दक्षता, नैतिकता और प्रतिभा आधारित नेतृत्व की बात कर रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उनके आंदोलन के अंतर्गत कोयंबटूर में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फोर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स की स्थापना का फैसला भी बताता है कि वह केवल चुनावी राजनीति नहीं, बल्कि वैचारिक और नैतिक प्रशिक्षण की स्थायी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। यह दृष्टिकोण तमिलनाडु की राजनीति में एक नई बौद्धिक धारा पैदा कर सकता है। उनके आह्वान के कुछ ही समय बाद हजारों लोगों का उनके राजनीतिक आंदोलन से जुड़ना यह संकेत देता है कि जनता के एक हिस्से में बदलाव की बेचैनी पहले से मौजूद थी। बताया जा रहा है कि अन्नामलाई ने भाजपा नेतृत्व के सामने दो स्पष्ट विकल्प रखे थे। एक तो उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता और अधिकारों के साथ कम से कम सात वर्षों तक प्रदेश नेतृत्व दिया जाए, या फिर उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक राह चुनने दी जाए। यह मांग उनके आत्मविश्वास और दूरदृष्टि दोनों को दर्शाती है। साथ ही इस्तीफे का ऐलान करने से पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से उनकी मुलाकात तथा पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें मनाने की कोशिश इस बात का प्रमाण है कि अन्नामलाई की अहमियत से भाजपा नेतृत्व वाकिफ है। वैसे तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति भी अन्नामलाई के लिए अवसर लेकर आई है। हालिया विधानसभा चुनावों में द्रविड़ दलों को झटके लगे और अभिनेता विजय की पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि राज्य की जनता अब पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से बाहर विकल्प तलाश रही है। अन्नामलाई का मानना है कि राष्ट्रीय दलों के लिए यहां सीमित राजनीतिक जगह है, इसलिए एक मजबूत क्षेत्रीय विकल्प ही जनता की आकांक्षाओं को सही दिशा दे सकता है। उनकी यह समझ राजनीतिक रूप से बेहद व्यावहारिक और दूरदर्शी मानी जा रही है। उधर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भले ही कहा हो कि अन्नामलाई के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक वास्तविकता इससे अलग दिखाई देती है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में भाजपा को ऊर्जा, आक्रामकता और जनस्वीकार्यता दी थी। अब उनके अलग होने से भाजपा के सामने नेतृत्व और जनाधार दोनों की चुनौती खड़ी होगी। दूसरी ओर, अन्नामलाई यदि अपने आंदोलन को संगठित ढंग से आगे बढ़ाते हैं तो वह तमिलनाडु की राजनीति में तीसरी शक्ति के रूप में तेजी से उभर सकते हैं। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि अन्नामलाई ने केवल पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति को नई दिशा देने की चुनौती स्वीकार की है। उनकी राजनीति में साहस है, वैचारिक स्पष्टता है और बदलाव की बेचैनी भी है। आने वाले वर्षों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या उनका यह आंदोलन तमिलनाडु की राजनीति में वैसा ही परिवर्तन ला पाएगा जिसकी वह कल्पना कर रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि अन्नामलाई ने राजनीति के मैदान में एक नई बहस छेड़ दी है। और इस बहस को नजरअंदाज कर पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा।

अन्नामलाई ने जिस साफगोई, साहस और वैचारिक दृढ़ता के साथ अपने फैसले को सामने रखा है, उससे यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब किसी दल के सीमित दायरे में नहीं, बल्कि तमिल समाज की व्यापक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप में उभरना चाहते है। अन्नामलाई ने खुलकर कहा कि उनके भीतर लंबे समय से यह संघर्ष चल रहा था कि वह पहले भारतीय है या तमिल। यह बयान केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के उस मूल द्वंद्व को सामने लाता है जिसमें राष्ट्रीय दलों को अक्सर क्षेत्रीय अस्मिता के सामने संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि चार दिसंबर 2025 को ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व को इस्तीफे का फैसला बता दिया था, लेकिन उनसे चुनाव तक रुकने का अनुरोध किया गया।

अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझें समाजवादी

देश और दुनिया आज एक नए चौराहे पर खड़ी है। एक ओर युद्ध और युद्ध विराम के बीच यूरोप और एशिया झूल रहा है तो दूसरी ओर देश भयानक आर्थिक संकट के मुहाने पर है। तीसरी ओर तमाम राष्ट्रों के भीतर और विशेषकर भारत में जाति और धर्म के आधार पर नफरती माहौल निर्मित हो गया है। चौथी लेकिन सबसे अहम बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित विश्व व्यवस्था टूट रही है। उसकी जगह पर कोई नई लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था बन नहीं रही है इसलिए नव उपनिवेशन का खतरा उपस्थित है। इसलिए यह समय समाजवादियों और विशेषकर एशियाई और भारतीय समाजवादियों के अपने विचार और संगठन के साथ उठ खड़े होने का है। भारत में समाजवादी आंदोलन के औपचारिक आरंभ के 90 साल हो रहे है। इसलिए इस विचार, आंदोलन और राजनीति से जुड़े लोगों को यह बता देना चाहिए कि उनके पास दुनिया को बेहतर बनाने का स्वप्न है और उनके पास इसका खाका भी है। अभी हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत का दौरा करके गए हैं। वे भारत को हिदायत देकर गए हैं कि उसे अपनी जरूरतों के लिए स्वतंत्र विकल्प के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बल्कि अमेरिका पर निर्भर हो जाना चाहिए और अमेरिका जो कहे उसे उसी दर पर खरीदना चाहिए जिस दर पर वह कहे। जाते जाते वे बता गए हैं कि वेनेजुएला की कठपुतली राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिग्स भारत का दौरा करेंगी। क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण कर रखा है और उनकी जगह पर शांति का नोबेल पाने वाली डेलसी को वहां का राष्ट्रपति बना रखा है। अमेरिका चाहता है कि वह वेनेजुएला का तेल निकाले और उसे दुनिया भर में महंगे दाम पर बेचे। इस तरह भारत अमेरिका की साम्राज्यवादी योजना का एक हिस्सा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने यूरोप में कहा था कि हमारी औपनिवेशिक परियोजना को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद झटका लगा था अब उसे फिर से शुरू करने का समय आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अपने पद की शपथ लेते ही एलान किया था कि कनाडा उनका 51 वां प्रांत है। उसी के साथ उन्होंने ग्रीनलैंड को भी हथियाने का प्रस्ताव यूरोप के सामने दे रखा है। ईरान पर हमला और उसकी तेल संपदा का दोहन उसकी इसी औपनिवेशिक परियोजना का हिस्सा है। क्यूबा जैसे पुराने प्रतिद्वंद्वी को भी ध्वस्त करने की तैयारी उसने कर रखी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा केसाथियों का यह दायित्व बनता है कि वह स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष में अपनी शानदार भूमिका का स्मरण करे और राष्ट्रवाद का झंडा संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी जैसी नकली राष्ट्रवादी शक्तियों से छीन कर उसे अपने हाथ में ले ले। आज समाजवादी पार्टी सिर्फ इसलिए जानी जाती है कि उसने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया और धर्मनिरपेक्षता का पक्ष लिया। उसने उसकी कीमत भी चुकाई है और उसके चलते प्रदेश और देश में अपनी जगह भी बनाई है। जनता ने उसके उस संघर्ष को सम्मान भी दिया है और यही वजह है कि आज वह लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। आज समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन का दायित्व महज उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत कर सरकार बनाकर कीर्तिमान स्थापित करने में है। पिछले लोक सभा चुनाव में जब भाजपा अबकी बार 400 पार का नारा लगा रही थी तब इण्डिया गठबन्ध और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उ0प्र. में भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का कार्य किया था आज उ0प्र0 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार बढ़ती हुई मंहगाई, बेकारी, बेरोजगारी, विद्यार्थियों किसानों महिलाओं अल्पसंख्यकों दलितों के उत्पीड़न के खिलाफगांधी वादी ढंग से गांव गांव गली गली चट्टी चौराहे पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन करना होगा, तभी प्रदेश में अघोषित आपातकाल का खात्मा हो पायेगा।डा0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है चाहे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, गोवा मुक्ति का आंदोलन हो या महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो समाजवादियों ने भारत के राष्ट्रवाद के निर्माण और संघर्ष में अपना सांगठनिक और वैचारिक योगदान दिया है। अंग्रेजों और अंग्रेजी साम्राज्य की नीतियों के हित में काम करने वाली मुस्लिम लीग और संघ परिवार ने इस देश का विभाजन किया और आज अपने को देशभक्त बताने वाले संघ परिवार ने फिर से साम्राज्यवादी योजना पर काम करते हुए भारत को आर्थिक रूप से अमेरिका पर निर्भर और सामाजिक राजनीतिक रूप से एक विभाजित देश बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वे पाकिस्तान के घर में घुस कर मारने का दावा करते हैं लेकिन इस मामले में अमेरिका के तमाम दावों का विरोध नहीं कर पाते। ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ और क्यों रुका इस बारे में सरकार कुछ साफ कहने की स्थिति में नहीं है। बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के युद्धविराम कराने के दावे और मध्यस्थता करने की कोशिशों पर भारत सरकार का मौन उनकी सत्तारूढ़ दल की देशभक्ति पर संदेह पैदा करता है। हाल में भाजपा के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी राम माधव का अमेरिका में हडसन डॉयलाग में यह कहना कि अमेरिका ने जो जो चाहा हमने वह कर दिया अब वह क्यों भारत के बारे में नस्ली टिप्पणियां करता रहता है। अमेरिका और विशेषकर उसके राष्ट्रपति ने भारत को नरक का गड्ढा कह कर राष्ट्रीय संप्रभुता का अपमान किया है लेकिन भारत सरकार ने उसका समुचित प्रतिवाद नहीं किया है। इन परिस्थितियों में समाजवादियों का यह दायित्व बनता है कि वे एक ओर चंद पूंजीपतियों के हित में बनाई जा रही भारत की आर्थिक नीतियों की कमियों को उजागर करें और उसके विकल्प में आत्मनिर्भर और आम जन के हित में सोचने और करने वाली समाजवादी नीतियों का विकल्प प्रस्तुत करें। एशियाई समाजवाद और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के दर्शन को देश दुनिया के सामने रखें। हमें याद रखना चाहिए कि डॉ राम मनोहर लोहिया ने दो बार अमेरिका की यात्रा की और वहां उन्होंने अमेरिकी सरकार नहीं अमेरिकी जनता से संबंध बनाने और उससे भारी अपेक्षा रखने की बात की। उन्हें सुनने और समझने वालों की भीड़ भी उमड़ी। उन्होंने वहां नस्लवाद यानी गोरे काले के भेद के विरोध में संघर्ष भी किया और गिरफ्तारी दी।

उन्होंने एक ऐसी विश्व व्यवस्था का विकल्प प्रस्तुत किया जो कि संयुक्त राष्ट्र से अलग और दुनिया भर से चुनकर आने वाले प्रतिनिधियों द्वारा संचालित थी। डॉ लोहिया जहां राष्ट्रों के बीच बराबरी की बात करते थे वहीं रंग, नस्ल, धर्म, लिंग, वर्ग और जाति पर आधारित भेदभाव को मिटाने का आह्वान करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि बीसवीं सदी में शुरू हुआ यह परिवर्तन इक्कीसवीं सदी में अच्छी तरीके से फलीभूत होगा। वैसा एक हद तक हुआ भी लेकिन आखिरकार पूंजीवादी शक्तियों ने स्वतंत्र देशों में आर्थिक संकट पैदा करके और फिर युद्ध छेड़ कर उस सपने को चकनाचूर कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति यह है कि दिल्ली और एन.सी.आर. में जहां पर तमाम कंपनियों के अधिकारियों को करोड़ों रुपए का सालाना वेतन मिलता है वहां के मजदूर दस हजार रुपए महीने में अपना परिवार चलाते हैं। जब वे विरोध करते है तो उन्हें पाकिस्तानी या अरबन नक्सल बता दिया जाता है। इसी प्रकार उर्वरक, तेल और गैस का जो संकट देश के सामने खड़ा हुआ है उससे किसान बेचैन है। उसे नहीं मालूम कि डब्लू अल नीनो प्रभाव के इस मौसम में उसकी उपज और आजीविका का क्या होगा। जाहिर सी बात है इन संकटों का बहुत मामूली हिस्सा प्रकृति प्रदत्त है।

इनका बड़ा हिस्सा पूंजीवादी शक्तियों और उनके साथ अमानवीय गठजोड़ करने वाली हथियार बेचने वाली औद्योगिक ताकतों ने पैदा किया है। आज देश में किसानों मजदूरों और युवाओं के बीच न तो बेचैनी की कमी है और न ही देशभक्ति की। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि बोस्टन में बैठे एक युवक ने काकरोच जनता पार्टी बनाई और देखते देखते उसके लाखों अनुयायी हो गए। अल्पसंख्यक समुदाय, किसान, आदिवासी और मजदूरों में भयानक असुरक्षा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वरुण ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/0882)

कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार, भारत रवाना हुए संस्थापक अभिजीत दीपके

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें पुलिस को शनिवार को जंतर-मंतर पर व्यंग्यात्मक संगठन कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर सभी प्रवेश गलियारों पर भीड़ नियंत्रण उपाय लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इस संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका से भारत आ रहे हैं, जिसके लिए पार्टी ने अनुमति नहीं ली है। सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका का उल्लेख न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी और अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष किया गया। एनजीओ के वकील ने अदालत से याचिका पर आज सुनवाई करने का आग्रह किया, हालांकि पीठ ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

'कॉकरोच जनता पार्टी' का शनिवार का विरोध प्रदर्शन

बोस्टन विश्वविद्यालय से स्नातक अभिजीत दिपके ने 15 मई को मुख्य न्यायाधीश द्वारा कुछ युवाओं को तिलचट्टे कहने के एक दिन बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट बनाए। कुछ ही दिनों में इसके इंस्टाग्राम पेज पर दस लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 8.8 मिलियन फॉलोअर्स से कहीं अधिक थे। अदालत की सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की तुलना तिलचट्टे और परजीवी से करने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत राष्ट्रीय चर्चा में आ गए। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी फर्जी डिग्री के साथ पेशे में प्रवेश करने वालों के लिए थी और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से उद्धृत किया गया था, लेकिन नुकसान या कहें कि मीम का जादू पहले ही हो चुका था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों के जवाब में एक व्यंग्यात्मक आंदोलन के रूप में शुरू हुई इस पार्टी ने तीन प्रवक्ताओं - खोजी पत्रकार सौरभ दास, राजनीतिक शोधकर्ता और फिल्म निर्माता विजेता दहिया और पूर्व प्रशांत सलाहकार आशुतोष पांडा - की नियुक्ति के एक दिन बाद बुधवार को दिल्ली में अपना पहला प्रेस सम्मेलन आयोजित किया।

फाउंडर भारत के लिए रवाना

इसके संस्थापक शुक्रवार को भारत के लिए रवाना हुए और शनिवार सुबह करीब 8 बजे दिल्ली पहुंचने की संभावना है। संगठन को युवाओं का भारी समर्थन प्राप्त है, जिसके चलते भारी भीड़ जुटने की आशंका है। इसी बीच, दिपके ने एक्स पर अपने समर्थकों से दिल्ली हवाई अड्डे पर न आने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, मैं संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए सीधे अनुमति लूंगा। उन्होंने कहा कि हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और हमें जिम्मेदारी से काम करना होगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे ध्यान रखें कि कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न करें।

मेगा प्लांटेशन अभियान का शुभारंभ, पर्यावरण दिवस पर सीएम रेखा ने की दिल्लीवालों से अपील

नई दिल्ली।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और सस्टेनेबल शहर बनाने के अपने संकल्प को दोहराया है। उन्होंने घोषणा की है कि इस विशेष अवसर पर दिल्ली सरकार एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव का शुभारंभ कर रही है। सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली को हरा-भरा और स्थायी शहर बनाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने प्रकृति के संरक्षण को हमारी समृद्ध संस्कृति और जीवनशैली का अभिन्न अंग बताते हुए सभी नागरिकों से इस पुनीत कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

एक पेड़ मां के नाम अभियान

इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव के तहत दिल्ली सरकार मिशन ग्रीन दिल्ली के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम नामक एक विशेष अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़कर एक पौधा लगाने की अपील की है। यह पहल न केवल पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल दिल्ली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

हरित दिल्ली, खुशहाल दिल्ली का संकल्प

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से हरित दिल्ली, खुशहाल दिल्ली के संकल्प को साकार किया जा सकेगा। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का आह्वान किया।

भारत के भू-राजनीतिक विस्तार से परेशान हैं राहुल गांधी, कांग्रेस नेता पर बीजेपी का पलटवार

नई दिल्ली। ग्रेट निकोबार विकास परियोजना की आलोचना करने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के बढ़ते भू-राजनीतिक प्रभाव से परेशान हैं। वह भारत के बजाय अन्य देशों को अधिक ताकतवर देखना चाहते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से यह टिप्पणी शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर राहुल गांधी के बयान के बाद आई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 16 मिनट से अधिक का एक वीडियो बयान पोस्ट किया। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के तर्क को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना रक्षा और पारगमन बंदरगाह के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक कारोबारी को लाभ पहुंचाने के लिए है, ताकि वह भारत की सबसे अहम पारिस्थितिक भूमि पर होटल और कसीनो बना सके। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि ग्रेट निकोबार परियोजना की परिकल्पना 1970 के दशक की गई है। उन्होंने कांग्रेस पर दशकों पहले ऐसी भविष्योन्मुखी परियोजनाओं की कल्पना करने के बावजूद उन्हें लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया। सिन्हा ने कहा, अगर कांग्रेस केवल ऐसी परियोजनाओं की कल्पना कर सकती थी, लेकिन उन्हें लागू करने में असमर्थ थी, तो यह निश्चित रूप से हमारी गलती नहीं है। सिन्हा ने कहा कि इस परियोजना के बनने से भारत की मौजूदगी हिंद महासागर में और दक्षिण की ओर करीब 400 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी हिस्से में बनने वाला बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के बहुत करीब होगा, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया का लगभग 30% समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसलिए अगर भारत का एक बड़ा बंदरगाह इसके पास होगा, तो वहां से गुजरने वाले जहाजों को सेवाएं देने, माल उतारने-चढ़ाने और व्यापार बढ़ाने में काफी फायदा होगा। सिन्हा ने ग्रेट निकोबार द्वीप के भू-रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया। राहुल गांधी ने चिंता जताई थी कि इस परियोजना से वहां रहने वाले आदिवासी (स्वदेशी) समुदायों और द्वीप के नाजुक पारिस्थितिकीतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। इस पर सिन्हा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी ग्रेट निकोबार द्वीप की केवल लगभग 10% जमीन का ही इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले 20 वर्षों में यहां चरणबद्ध तरीके से करीब 3.5 लाख से 4 लाख लोगों को बसाने की योजना है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस विकास कार्य के दौरान पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन से जुड़ी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। सिन्हा ने जोर देकर कहा कि भारत केवल इसलिए भविष्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनमें आदिवासी क्षेत्र शामिल है।

भालौट व झज्जर सब ब्रांच के पुनर्निर्माण कार्य को मिली नई गति, किसानों और नहर विभाग के बीच बनी सहमति - श्रुति चौधरी

चंडीगढ़। (संवाददाता) हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी के प्रयासों से भालौट सब ब्रांच एवं झज्जर सब ब्रांच के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। किसानों, ग्रामीणों और नहर विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार संवाद एवं सकारात्मक पहल के परिणामस्वरूप सभी पक्षों के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी है, जिससे अब दोनों नहरों के पुनर्निर्माण कार्य को दोबारा गति मिलेगी। श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा करते हुए सिंचाई ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास कार्य की सफलता तभी संभव है जब उसमें स्थानीय लोगों की भावनाओं, सुझावों और आवश्यकताओं का सम्मान किया जाए। इसी सोच के तहत किसानों की चिंताओं को गंभीरता से सुना गया और सभी पक्षों को साथ लेकर समाधान का रास्ता निकाला गया। गौरतलब है कि भालौट एवं झज्जर सब ब्रांच से जुड़े अनेक गांवों के किसानों और ग्रामीणों ने नहर के तल को पूरी तरह सीमेंट-कंक्रीट से पक्का किए जाने पर आपत्ति जताई थी। किसानों का कहना था कि ऐसा होने से भूजल पुनर्भरण (रिचार्ज) प्रभावित हो सकता है तथा क्षेत्र के जल संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। किसानों की इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए नहर विभाग ने विभिन्न तकनीकी विकल्पों पर विचार-विमर्श किया और लगातार संवाद की प्रक्रिया जारी रखी। आज की बैठक में जौली-लाठ, तेवड़ी, रैठल, चौड़ी, घामड़, किलोई, बोहर, मकड़ौली, माखना सहित आसपास के गांवों के किसानों और ग्रामीणों ने भाग लिया। विस्तृत चर्चा के बाद यह सहमति बनी कि नहर के तल को 10 फुट तक कंक्रीट लाइनिंग के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जबकि शेष हिस्से में ब्लॉक लाइनिंग की जाएगी। साथ ही किसानों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दो पुलों के बीच सीढ़ियों का निर्माण तथा प्रत्येक पुल के साथ घाट विकसित किए जाएंगे।

फरीदाबाद में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में बड़ा कदम, 45 नए ईको वन होंगे विकसित - कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल

(संवाददाता)

चंडीगढ़। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हरियाणा के राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए इसे जनआंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए आज से ही सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

श्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रकृति और संस्कृति को जोड़ने वाला एक प्रेरणादायी अभियान है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए तथा उसके संरक्षण का भी संकल्प ले।

ग्रीन बेल्ट को बनाया जाएगा ऑक्सीजन कॉरिडोर, प्रदूषण नियंत्रण को मिलेगी मजबूती

केवल वृक्षारोपण ही नहीं, बल्कि पौधों को विकसित कर वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी भी समाज को निभानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी और विरासत भी के विजन के अनुरूप देशभर में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी सतत विकास, हरित भविष्य और स्वच्छ पर्यावरण के लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। श्री विपुल गोयल ने घोषणा करते हुए कहा कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आगामी 15 दिनों के भीतर 45 नए ईको वन विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पहले से विकसित 15 ईको वन सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या 100 से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि ईको वन केवल हरियाली बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, तापमान संतुलन और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन हरित क्षेत्रों से पक्षियों का प्राकृतिक आवास विकसित होता है तथा शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन को नई मजबूती मिलती है। श्री विपुल गोयल ने समाजसेवियों, उद्योगपतियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों से ईको वन अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि जनभागीदारी से ही ऐसे अभियान स्थायी और सफल बनते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण अभियान की सबसे मजबूत आधारशिला है और यदि युवा एक पौधा लगाने के साथ-साथ उसके संरक्षण का संकल्प लें तो हरियाणा का पर्यावरण और अधिक समृद्ध एवं संतुलित बन सकता है। कार्यक्रम के दौरान वेस्ट मैनेजमेंट पार्क का उद्घाटन एवं विभिन्न पर्यावरणीय गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं। वेस्ट मैनेजमेंट पार्क जैसी पहलें स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाने का कार्य करेंगी। उन्होंने अंत में कहा कि जल है तो कल है केवल एक नारा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हम सभी को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, ऊर्जा बचत और अधिकाधिक वृक्षारोपण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। सामूहिक प्रयासों से ही अपने शहरों को स्वच्छ, हरित, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाया जा सकता है।

हरित क्रांति की तरह बागवानी एवं एग्री-बिजनेस क्रांति का अब नेतृत्व करेगा हरियाणा-मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़। (संवाददाता) हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हरियाणा को बागवानी, एग्री-बिजनेस, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी मिलकर कृषि को अधिक टिकाऊ, आधुनिक और लाभकारी बनाने, जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंचकूला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2,738 करोड़ रुपये की लागत से जाइका वित्तपोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ तथा हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का शिलान्यास के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं न केवल किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, बल्कि हरियाणा की कृषि व्यवस्था को आधुनिक, टिकाऊ एवं लाभकारी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ इस दौरान प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद थे। दोनों ने इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण भी किया, साथ ही बागवानी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जीआईसीए के मुख्य प्रतिनिधि श्री टाकेची टकूरो, फर्स्ट सेकेट्री फूड एंड एग्रीकल्चर श्री टाकेहिको हयासे तथा ब्रिटिश डिप्टी हाईकमीश्नर ऐलबा स्मीरिलयो मौजूद थे। तीनों ने अपने संबोधन में हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में उठाये गये कदमों की तारीफ की।

उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन केवल दो परियोजनाओं के शुभारंभ का नहीं, बल्कि हरियाणा के कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक नई दिशा तय करने का दिन है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा एक बार फिर देश को नई राह दिखाएगा और हरित क्रांति की

मुख्यमंत्री ने 2,738 करोड़ रुपये की सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का किया शुभारंभ, हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर की रखी आधारशिला

हरियाणा में 402 पैक हाउस, 4 लीड पैक हाउस बनेंगे, बागवानी के किसान होंगे मालामाल

जापान के कोची विश्वविद्यालय से हरियाणा के किसानों को मिलेगी अनुसंधान की विश्वस्तरीय तकनीक

विश्व पर्यावरण दिवस पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत किया पौधारोपण

तरह बागवानी एवं एग्री-बिजनेस क्रांति का नेतृत्व भी करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने देश को हरित क्रांति दी थी, लेकिन बदलती जलवायु, गिरते भूजल स्तर, बढ़ती कृषि लागत और छोटी जोत जैसी चुनौतियों को देखते हुए अब कृषि क्षेत्र में नए विकल्प अपनाने की आवश्यकता है। बागवानी, फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय पौधे, फूल, मशरूम और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में किसानों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में जलभराव एवं सेम की समस्या के समाधान के लिए बायोड्रेनेज तकनीक का उपयोग करते हुए इस वर्ष 1,000 हेक्टेयर जलभराव प्रभावित भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा, जिससे भूमि पुनः कृषि योग्य बन सकेगी। इसके साथ ही भूमिगत जल संरक्षण के लिए शिवालिक एवं अरावली क्षेत्रों में 25 नए जल भंडारण बांध बनाए जाएंगे तथा 25 पुराने बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

हरियाणा में 402 पैक हाउस, 4 लीड पैक हाउस बनेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में फलों और सब्जियों का 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा खेत से बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। इस चुनौती का समाधान सतत बागवानी संवर्धन परियोजना के माध्यम से किया जाएगा।

परियोजना के तहत 400 बागवानी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, 500 उत्पादक समूहों को संगठित एवं सशक्त बनाया जाएगा, 402 पैक हाउस, 4 लीड पैक हाउस, 3 फुलफिलमेंट सेंटर तथा 44 रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 1,000 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा तथा 65,000 एकड़ क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना खेत से बाजार तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगी तथा आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होगा।

परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वास्तविक समय निगरानी प्रणाली, मिट्टी एवं जल विश्लेषण, डिजिटल कृषि सलाह, इंटरनेट ऑफ प्लांट्स, भू-स्थानिक तकनीक, ई-मार्केटिंग और आधुनिक पैकेजिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल तथा जापान के कोची विश्वविद्यालय के बीच ज्ञान एवं अनुसंधान के आदान-प्रदान से किसानों को विश्वस्तरीय तकनीकी सहायता उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि कृषि अब केवल खेती तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक बड़ा व्यवसाय बन चुकी है, जिसमें ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट सेंसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स जैसी तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

नौकरी देने वाले बने युवा

उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे नौकरी मांगने के बजाय एग्री-बिजनेस, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उद्योग और निर्यात आधारित उद्यमों के माध्यम से रोजगार सृजनकर्ता बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हरियाणा के निर्माण में महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर किसानों, एफपीओ, उद्यमियों, स्टार्टअप्स और कृषि विशेषज्ञों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे 3 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में 75 प्रतिशत से अधिक सुधार होगा तथा कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 10 से 15 प्रतिशत तक कमी आएगी। जीएपी, जीएमपी, जीएचपी तथा एचएसीसीपी जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाकर कृषि निर्यात को भी नई गति मिलेगी।

हालसा मानसून सीज़न में राज्य में 10 लाख पौधे रोपित करेगा

चंडीगढ़। (संवाददाता) पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा भर में एक राज्यव्यापी वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत वन विभाग के सहयोग आगामी मानसून सीज़न के दौरान राज्य भर में लगभग 10 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ करते हुए, न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों-एवं-अध्यक्षों तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट्स-एवं-सचिवों से बातचीत करते हुए उन्हें पौधारोपण अभियान के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह पहल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए एक हरित एवं पर्यावरण अनुकूल भविष्य को बढ़ावा देने और भावी पीढ़ियों के लिए जीवंत एवं स्वस्थ पर्यावरण की विरासत सुनिश्चित करने में सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने न्यायालय परिसरों, एडीआर केंद्रों, न्यायिक आवासीय परिसरों तथा अन्य उपलब्ध सार्वजनिक स्थानों पर उपयुक्त स्थानों की पहचान करके जिलों में व्यापक वृक्षारोपण गतिविधियों को शुरू करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वृक्षों का संरक्षण और पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका रोपण। उन्होंने वृक्षों के संरक्षण, पोषण एवं स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के लिए पौधों की उचित देखभाल, रखरखाव और निगरानी की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। माननीय न्यायाधीश ने निर्देश दिए कि वृक्षारोपण अभियान को व्यवस्थित और परिणाम प्रेरित तरीके से चलाया जाए, जिसमें स्कूली बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिक परिस्थितियों के अनुकूल स्वदेशी, औषधीय, फलदायी और छायादार प्रजातियों के पौधे लगाए जाएं। इस पहल का उद्देश्य केवल हरित आवरण बढ़ाना ही नहीं, बल्कि जैव-विविधता को मजबूत करना और पूरे राज्य में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना भी है। उन्होंने हरियाणा के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि वे प्रभावी निगरानी और यथार्थवादी परिणामों के लिए इस पहल की प्रगति के संबंध में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री जगदीप सिंह ने कहा कि यह अभियान केवल एक प्रतीकात्मक अभ्यास बनकर न रह जाए, बल्कि एक सतत पर्यावरण आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित हितधारकों से अनुरोध किया कि वे रोपित पौधों की कम से कम पांच वर्षों तक उचित देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि वे स्वस्थ रूप से विकसित होकर परिपक्व वृक्ष बन सकें। उन्होंने सभी हितधारकों और आम जनता से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और एक हरित एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक हरियाणा के निर्माण में योगदान देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करने, पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और पूरे हरियाणा राज्य में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वृक्षारोपण महाअभियान को हरियाणा के सभी सत्र मंडलों में मिशन मोड के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एवं-सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जगदीप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला संजय संधीर, संयुक्त सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मानविका यादव तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला अजय कुमार भी उपस्थित थे।

हरियाणा में अब गुणवत्ता की होगी डिजिटल चौकीदारी, क्यूएए बदल रहा है निर्माण कार्यों का पूरा सिस्टम

चंडीगढ़। (संवाददाता) हरियाणा में विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण एक मजबूत और तकनीक आधारित निगरानी तंत्र विकसित कर रहा है। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा बनाये जाने वाले हर प्रोजेक्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए निर्माण कार्यों की निगरानी, परीक्षण और मूल्यांकन की पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। बकायदा इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग विशेष तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिसमें परियोजना की योजना, डिजाइन, डीपीआर, निर्माण और रखरखाव के प्रत्येक चरण की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा सके। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी समय–समय पर इस संबंध में विशेष बैठक लेते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं तथा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी निर्देश की अनुपालना को आगे बढ़ाते हुए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण (क्यूएए) विशेष रणनीति के तहत काम कर रहा है। छोटे से लेकर बड़े काम पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है, समय समय पर औचक निरीक्षण भी हो रहे हैं। निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्री की जांच के लिए विशेष लैब भी बनाई जा रही है। श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि क्यूएए का उद्देश्य केवल कमियों को उजागर करना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग विभागों में गुणवत्ता आधारित कार्य संस्कृति को विकसित करना है। इसी दिशा में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का तकनीकी ऑडिट किया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। सभी प्रमुख परियोजनाओं में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एवं मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक परियोजना स्थल पर क्यूआर कोड आधारित सूचना प्रणाली लागू करने की योजना है। इससे नागरिक परियोजना की लागत, अवधि, एजेंसी और प्रगति संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, परियोजनाओं के अनावश्यक विभाजन पर रोक लगाने और डिजाइन स्तर पर ही ड्रेनेज एवं जल निकासी जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं को शामिल करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के लिए अधिकारियों और इंजीनियरों के व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब हरियाणा सार्वजनिक आधारभूत ढांचा विकास में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के नए मानक स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की जनता को बड़ी सौगात

चंडीगढ़। (संवाददाता) हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के प्रयासों से प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार ने जहां 200 बेड के जिला नागरिक अस्पताल, पानीपत के लिए 122 नियमित पदों तथा 97 पद हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से भरने सहित कुल 219 पदों के सृजन एवं स्वीकृति प्रदान की है, वहीं जिला कुरुक्षेत्र के उप-स्वास्थ्य केंद्र थाना को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में अपग्रेड करने की मंजूरी भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन निर्णयों से लोगों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि पानीपत के 200 बेड के नागरिक अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 122 नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, डेंटल सर्जन, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर सहायक, डाइटीशियन, बायो मेडिकल इंजीनियर, सोशल वर्कर तथा जनसंपर्क अधिकारी सहित विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अस्पताल की सहायक सेवाओं को मजबूत करने के लिए 17 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 37 स्वीपर, 37 वार्ड सर्वेंट, 5 सुरक्षा गार्ड तथा 1 सुपरवाइजर के पद हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से भरे जाएंगे। इन पदों के सृजन से अस्पताल में मरीजों को अधिक प्रभावी एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं कुरुक्षेत्र जिले के थाना उप-स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किए जाने से क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

होटल-कैसीनो के लिए कट रहे पेड़ - ग्रेट निकोबार परियोजना पर राहुल ने उठाए सवाल, कहा- अदाणी की मदद कर रही सरकार

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह दावा है कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना रक्षा और माल ढुलाई बंदरगाह से संबंधित है। यह एक झूठ है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि यह असल में भारत की सबसे अमूल्य पारिस्थितिक भूमि पर एक व्यवसायी को होटल और कैसीनो बनाने में मदद करने के बारे में है। राहुल गांधी ने अप्रैल के अंत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा पर आधारित 16 मिनट से अधिक का एक वीडियो जारी किया। एक्स पर वीडियो के साथ अपनी पोस्ट में गांधी ने कहा, "मैंने भारत के सबसे दक्षिणी छोर का दौरा किया। मैं इंदिरा प्वाइंट पर खड़ा हुआ। मैं सदियों पुराने पेड़ों के नीचे चला। मैं पृथ्वी पर सबसे जीवंत प्रवाल भित्तियों में गोता लगाया। मैं वहां रहने वाले लोगों के साथ बैठा। आदिवासी समुदाय, जिनकी जमीन वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करके छीनी जा रही है। भारतीय सरकार द्वारा इन द्वीपों पर बसाए गए कई पूर्व सैनिक, जिन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है।'

आईएनएस बाज का विस्तार कीजिए, हम साथ हैं

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, मोदी सरकार और भाजपा आपको बताते हैं कि ग्रेट निकोबार परियोजना रक्षा से संबंधित है। ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा आईएनएस बाज का विस्तार कीजिए। हम सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। नौसेना पिछले पांच वर्षों से विस्तार की मांग कर रही है, जिसे नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बता रही है कि यह परियोजना एक माल परिवहन बंदरगाह के बारे में है। जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत पहले से ही केरल में एक ऐसा संयंत्र बना रहा है, जो मुख्य भूमि पर स्थित है। उन्होंने आरोप लगाया, वास्तव में हुआ यह है- 1.5 करोड़ पेड़ काटे गए। सरकारी नक्शों से प्रवाल भित्तियों को मिटा दिया गया। मैंग्रोव और आदिवासियों को विस्थापित किया गया। क्योंकि एक व्यवसायी भारत की सबसे अमूल्य पारिस्थितिक भूमि पर होटल और कैसीनो बना सके। उन्होंने कहा, मैंने जिन भी युवा भारतीयों से बात की है वह सभी इस बात को समझते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी तरह का मुनाफा उस चीज को नष्ट करने के लायक नहीं है जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता।

हजारों पेड़ों को काट कर बाहर भेजते हैं

गांधी ने कहा कि वह पारिस्थितिक रूप से संतुलित विकास के पक्षधर हैं। उन्होंने दावा किया कि ये द्वीप दुनिया के सबसे असाधारण टिकाऊ पर्यटन स्थल बन सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यही वह भारत है जिसके लिए लड़ना सार्थक है। यह वह है जो मोदी नहीं चाहते कि आप देखें। योजना क्या है?

लखीमपुर खीरी से देहरादून जा रही निजी बस पलटी- एक की मौत, 30 अन्य घायल

नेशनल डेस्क । उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से उत्तराखंड के देहरादून जा रही एक निजी बस शुक्रवार को यहां डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दुर्घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के रोशनपुर प्रताप में उस समय हुई जब बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के समय बस में 65 यात्री सवार थे। उन्होंने बताया कि हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जिसकी पहचान लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा थाना क्षेत्र के तेलया गांव निवासी राकेश (30) के रूप में हुई है।

अराजकता में अवसर खोजने की सियासत नहीं चलेगी- पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कर्नाटक से बंगाल तक का जिक्र

हजीरा (गुजरात)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात दौरे पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चल रही विकास परियोजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने सूरत के हजीरा के अलावा अंतरराज्यीय रोड नेटवर्क का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ लोग देश में निराशा का माहौल बनाने में लगे हैं। पीएम मोदी ने विपक्षी राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया और बिना किसी का नाम लिए कहा कि ये लोग निराशा का माहौल बनाने के अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक भी बनाते हैं। उन्होंने कांग्रेस या राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, कुछ लोग भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं।

कांग्रेस ने कर्नाटक में बदला मुख्यमंत्री, पीएम मोदी क्या बोले?

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली सफलता का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान भी उन्हें बंगाल के जनादेश का जिक्र सुनने को मिला। हाल ही में कर्नाटक में बदले मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस राज्य में भी कांग्रेस को लेकर जनता में भारी आक्रोश है।

जनता ने कांग्रेस को हाशिए पर धकेला

पीएम मोदी ने भाजपा को मिलने वाली राजनीतिक सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस पिछले 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैला कर अपने लिए अवसर तलाश रही है, लेकिन देश की जनता बार-बार करारा जवाब दे रही है। आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां की जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुकी है।

हिमाचल, हरियाणा और पंजाब की जनता ने भी कांग्रेस को नकारा

हिमाचल में हुए निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, वहां की जनता ने भी कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया। पिछले साल हरियाणा और पंजाब की जनता ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है। जनता ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की अराजकता में अवसर खोजने की राजनीति नहीं चलेगी।

हिमाचल प्रदेश के चंबा में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.0 आंकी गई तीव्रता

शिमला। हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा में शुक्रवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.0 आंकी गई. चंबा और कांगड़ा जिले के अलावा भी आसपास के कई इलाकों में लगभग पांच सेकंड तक लोगों ने भूकंप के बड़े झटके महसूस किए. भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकल गए. हालांकि अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है. शुरुआती जानकारी के अनुसार भूकंप 10 बजकर 4 मिनट पर आया. वहीं भूकंप का केंद्र भरमौर के आसपास बताया जा रहा है और गहराई 5 किलोमीटर थी. वहीं तीव्रता 5.0 आंकी गई. भारतीय उपमहाद्वीप में

भूकंप की गतिविधियां सामान्य मानी जाती है क्योंकि भारत कई सक्रिय फॉल्ट लाइनों पर स्थित है. उत्तर-पूर्वी भारत सहित हिमालय रेंज भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है. यह क्षेत्र भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टेक्टॉनिक गतिविधियों के कारण बार-बार कंपन महसूस करता रहता है.

फायरिंग मामले में हो सकती है खान सर की गिरफ्तारी

पटना । पटना में फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। कदमकुआं थाने में फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीएनएस की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। एफआईआर के बाद खान की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे। इधर, लॉ-एंड-ऑर्डर को लेकर हाई ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में ना आएं। वहीं, सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स खान सर की कोचिंग के

बाहर जुटे और समर्थन में नारेबाजी की। दरअसल, 2 जून की रात पटना स्थित खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ था। पटना के दौरान उनके बॉडीगार्ड्स के फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आया था। मामले में पुलिस पहले ही दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और खान सर से भी पूछताछ की जा चुकी है। हमले वाले दिन खान सर ने पुलिस की जमकर तारीफ की थी। अब उन्होंने कहा कि पुलिस लेट पहुंची। गार्ड्स के फायरिंग वाले वीडियो पर खान सर ने कहा, मारपीट हो रही थी। मुझे पता था पुलिस को पहुंचने में समय लगेगा। पुलिस वहां उड़कर तो नहीं पहुंचती, इसलिए गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। गार्ड क्यों रखते हैं ताकि समय पड़े तो लोगों को बचा सकें। जब तक पुलिस नहीं आई थी तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए था। क्या गार्ड्स ने किसी पर फायरिंग की।इससे पहले खान सर का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो क्लासरूम में बच्चों को अपने कोचिंग पर हुए हमले के बारे में बता रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बच्चों को बता रहे हैं कि जो कोचिंग के गार्ड को लेकर जा रहा है उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। मुद्दे से भटकाया जा रहा है। खान सर ने ये भी कहा कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज बंद हो गया तो अगले 6 महीनों में कई कोचिंग संस्थानों की फीस एक लाख से डेढ़ लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है।

कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान को घेरा, पूछा- बोर्ड के विरोध के बाद भी महंगे रेट पर क्यों दिया ठेका

नई दिल्ली ।

कांग्रेस ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बोर्ड पर महंगी ओएसएम प्रणाली लागू की गई और इस प्रक्रिया में लागत बढ़ने को लेकर उठे सवालों का जवाब केवल शिक्षा मंत्री ही दे सकते हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि दिसंबर 2024 में हुई सीबीएसई गवर्निंग बॉडी की बैठक में ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली लागू करने से होने वाले वित्तीय बोझ पर चिंता जताई गई थी। इसके बावजूद इस व्यवस्था को लागू किया गया।

टेंडर लागत बढ़ने का आरोप

जयराम रमेश ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि ओएसएम सिस्टम से जुड़े टेंडर की अनुमानित लागत में करीब 10

करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। उनके अनुसार, सीबीएसई द्वारा जारी शुरुआती दो टेंडरों में कार्य का मूल्य 28 करोड़ रुपये था, लेकिन अंतिम वर्क ऑर्डर में यह बढ़कर 38.46 करोड़ रुपये हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि वास्तविक रूप से स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर इस कार्य की लागत लगभग 25.39 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी, जो जारी वर्क ऑर्डर की राशि से काफी कम है।

संसदीय समिति के सामने उठे सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में 18 वर्षीय व्हिसलब्लोअर सार्थक सिद्धांत की बात सुनने के बाद समिति ने सीबीएसई से खरीद प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल पूछे थे, लेकिन बोर्ड इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। रमेश ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए कि आखिर सीबीएसई को इतनी महंगी ओएसएम प्रणाली अपनाने के लिए क्यों कहा गया।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

कांग्रेस ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय जांच समिति केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी।

राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने ओएसएम विवाद के बाद सीबीएसई के शीर्ष अधिकारियों को हटाए जाने को लीपापोती और सच्चाई छिपाने की कोशिश बताया है। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री को पद से हटाने और पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

पीएम मोदी ने गिनाईं भारत की उपलब्धियां, हरित क्षेत्र और वन्यजीवों की आबादी में हुआ रिकॉर्ड इजाफा

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए पिछले एक दशक में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत द्वारा हासिल की गई ऐतिहासिक सफलताओं को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की निरंतर नीतियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों के चलते देश के हरित आवरण का विस्तार हुआ है और कई दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों की आबादी में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयासों, नीतियों, विज्ञान में विश्वास और नवाचार के माध्यम से पर्यावरण में सुधार लाने के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नागरिकों की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों की मैं सराहना करता हूं।''मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह दिन हमें ''अपने पर्यावरण की रक्षा करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने की याद दिलाता है''।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक से राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, बोले- सर्वसम्मति से मुझे चुना गया

बंगलूरू । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बंगलूरू स्थित विधान सौधा में उन्होंने विधानसभा सचिव एमके विशालाक्षी के समक्ष नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन दाखिल करने के बाद खरगे ने कहा कि आज मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। सभी विधायकों और मेरे नेताओं ने सर्वसम्मति से मुझे चुना है। चुनाव 18 जून को होने है और मुझे विश्वास है कि सभी एकजुट रहेंगे और कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस महासचिव

रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। खरगे वर्तमान में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने पुनः उच्च सदन के लिए नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस ने कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और एआईसीसी सचिव मंसूर अली खान को भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, दोनों नेता जल्द ही अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मंसूर अली खान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगलूरू सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है।

अन्नामलाई के बाद 14 से अधिक पार्टी पदाधिकारियों ने भी दिया इस्तीफा

चेन्नई।

अन्नामलाई के इस्तीफे का असर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दिखने लगा है। अब तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष के नागराजन, राज्य सचिव सुमति वेंकटेश और पार्टी के 14 पदाधिकारियों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे राज्य भाजपा इकाई में संकट और गहराता नजर आ रहा है।

अन्नामलाई की ओर से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से औपचारिक रूप से इस्तीफा देने और एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही ये इस्तीफे आए। अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु के लिए उनका सियासी नजरिया अब पार्टी नेतृत्व के विचारों से मेल नहीं खाता। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में अन्नामलाई राज्य में पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरे थे। अन्नामलाई

भाजपा को बड़ा झटका?

ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2025 में ही पार्टी नेतृत्व को अपने इस्तीफे के इरादे की जानकारी दे दी थी।

इस्तीफे के बाद अन्नामलाई ने क्या कहा?

अन्नामलाई के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व ने उनसे अनुरोध किया था कि वे विधानसभा चुनाव अभियान पूरा होने तक पार्टी में बने रहें। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक लक्ष्य और बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए एक ऐसे नए और समावेशी मंच की जरूरत है, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले।

क्या है अन्नामलाई की भविष्य की योजना?

उन्होंने यह भी बताया कि वह एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने और भविष्य में राज्य के चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिये अपने संबोधन में अन्नामलाई ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु के प्रति पार्टी के दृष्टिकोण को लेकर मतभेद होने के बावजूद उन्होंने भाजपा को सौहार्दपूर्ण तरीके से छोड़ा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने कहा कि उनका नया राजनीतिक आंदोलन व्यक्ति पूजा की राजनीति और वंशवादी राजनीति को खत्म करने पर फोकस करेगा। साथ ही यह तकनीकी विशेषज्ञों, पेशेवरों और आम नागरिकों को शासन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा। अन्नामलाई के समर्थकों ने उनके फैसले का स्वागत करते हुए पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटीं।

अन्नामलाई की ओर से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से औपचारिक रूप से इस्तीफा देने और एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही ये इस्तीफे आए। अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु के लिए उनका सियासी नजरिया अब पार्टी नेतृत्व के विचारों से मेल नहीं खाता।

अन्नामलाई के इस्तीफा का असर नहीं- नैनार नागेंद्रन

वहीं, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने इस्तीफे को लेकर चिंताओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा एक विचारधारा आधारित संगठन है और अन्नामलाई के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। नागेंद्रन ने कहा, अन्नामलाई के इस्तीफे का भाजपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकतंत्र में किसी को भी नई राजनीतिक पार्टी बनाने की आजादी है। अन्नामलाई का इस्तीफा ऐसे समय में आया है, जब 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन दोबारा शुरू होने के बाद उन्हें तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। एआईएडीएमके के कुछ नेताओं के साथ अन्नामलाई के संबंध विवादित बयानों और वैचारिक मतभेदों के कारण पहले से ही तनावपूर्ण रहे थे। करु नागराजन और कई अन्य पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद अब यह अटकलें तेज हो गई हैं कि आने वाले हफ्तों में और भी नेता तथा कार्यकर्ता अन्नामलाई की प्रस्तावित नई राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं।

मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावना जल्द

नई दिल्ली । दो केंद्रीय मंत्रियों को फिर से राज्यसभा में नहीं भेजने के बीजेपी के फैसले के बाद मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलों ने फिर जोर पकड़ लिया है. प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष अगले सप्ताह नौ जून को पूरे करने जा रहे हैं. अगर उनके अब तक के कार्यकाल में किए गए मंत्रिमंडल विस्तारों को देखा जाए तो इस बात की संभावना जोर पकड़ रही है कि आने वाले दिनों में मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो सकता है. अगले साल पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अटकलें लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इन्हें ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे.

किन राज्यों में होने वाले हैं चुनाव

अगले साल पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. इनमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं. जिस तरह से पंजाब से आने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को फिर से राज्यसभा सीट नहीं देने का फैसला किया गया है, उससे संकेत मिल रहा है कि पंजाब से किसी अन्य चेहरे को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है. पंजाब से आने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण चुग को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया है. इसी तरह कुछ अन्य मंत्रियों का

9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. उनके मौजूदा कार्यकाल के दो साल पूरे होने वाले हैं. ऐसे में मंत्रिपरिषद में बदलाव की चर्चाएं स्वाभाविक रूप से तेज हो गई हैं.

राज्यसभा कार्यकाल भी इस साल पूरा हो रहा है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद है. उनका कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है. इसी तरह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री बी एल वर्मा भी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है और उनका कार्यकाल भी 25 नवंबर तक है.

किन राज्यों के नेताओं को फायदा

उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर इस साल के अंत में चुनाव होना है. जबकि अगले साल की शुरुआत में यूपी में विधानसभा चुनाव होगा. उसी के साथ उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के भी चुनाव कराए जाएंगे. जबकि अगले साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे. संभावना है कि मंत्रिपरिषद फेरबदल में इन राज्यों से कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है. कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाए जाने या फिर उनके विभाग बदलने की भी संभावना है. हाल की मंत्रिपरिषद बैठक में कैबिनेट सचिव ने सभी मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था. इसमें जन शिकायत के समाधान और सुधारों को लेकर पांच सबसे बेहतरीन मंत्रालयों के नाम भी बताए गए थे. फाइलों को निपटाने में लगने वाले समय और अदालतों में लंबित मामलों को लेकर भी मंत्रालयों को कसौटी पर कसा गया था. माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल में यह आकलन एक बड़ी भूमिका निभाएगा.

इन नेताओं की हो सकती है छुट्टी

माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिपरिषद में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, क्योंकि वहां बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई है. इसी तरह बिहार से कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को जगह मिलने की संभावना है. उत्तर प्रदेश से भी कुछ नए चेहरे आ सकते हैं. सूत्रों के अनुसार सहयोगी दलों का कोटा फिलहाल मौजूदा स्तर पर ही रहेगा. यानी सहयोगी दलों से कोई नया मंत्री बनाए जाने की संभावना नहीं है. सत्तर वर्ष के अधिक उम्र के कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना है. कुछ मंत्रियों को पार्टी संगठन में भेजे जाने की भी चर्चा है. कहा जा रहा है कि इस बार मंत्रिपरिषद का फेरबदल बड़े स्तर पर होगा, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम हो सकते है.